International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-3 May-June-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

मुरली धर सिंह
पी–एच.डी. शोधछात्र
शिक्षा संकाय
ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर
उत्तर प्रदेश

डॉ. वी. के. शर्मा
प्रोफेसर – शिक्षा संकाय
ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर
उत्तर प्रदेश

सारांश

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। बालक की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्राथमिक शिक्षा स्तर कहा जाता है। प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ भारत सरकार के सहयोग से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने हेतु मिशन के रूप में किया गया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए मुख्यतः सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था है। इन दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की सुविधाओं, शिक्षण की तकनीकी, शिक्षक की योग्यता, विद्यार्थी की आर्थिक सामाजिक स्थिति एवं विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली सुविधाओं आदि में अन्तर होता है। इन सभी परिस्थितियों को बालकों के मानसिक एवं सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है।प्रस्तुत प्रपत्र में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी है।

प्रस्तावना– शिक्षा मानव के जीवन की आधार शिला है। मानव का विकास और उन्नति शिक्षा पर ही निर्भर है, शिक्षा व्यतिव का निर्माण भी करती है। जन्म के समय बालक पशुत्व आचरण करता है उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों को उचित मार्गदर्शन करके परिपक्वता प्रदान करती है। बालक एवं उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाजोपयोगी बनाती है। शिक्षा उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। यदि शिक्षा का अर्थ अधिक समझें तो यही है कि शिक्षा ही वह गुरु तथा दीपक है, जो कि मनुष्य को सही पथ दिखाती है तथा जिसकी दिशा तथा रोशनी को अपनाकर खुद को समाजपयोगी बनाकर समाज को विकास की ओर अग्रसर करता है, तो यह गलत न होगा। भारत जैसा एक लोकतांत्रिक तथा बहुजनसंख्या वाले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुचाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर समझा जा रहा है। इस अधिनियम को सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चों को, बाल मजदूरों प्रवासी बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारको की वजह से वंचित बच्चों में शामिल है। शिक्षा के द्वारा मानव केवल अपने वातावरण से अनुकूलन करने में ही समर्थ नहीं होता वरन् वातावरण और प्रकृति पर विजय प्राप्त

करने का भी प्रयत्न करता है। शिक्षा ही मानव का असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और निर्देशित करती है। शिक्षा ही व्यक्तित्वता की केंचुली से बाहर लाकर मानव को इस योग्य बनाती है कि वह समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण संसार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपना सके और अपने कर्तव्यों का निर्वाहन भली प्रकार से कर सके। शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य की उन छिपी हुई तथा आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर उनका उपयोग समाज, देश राष्ट्र की भलाई में लगाते हैं यानि शिक्षा वह मथनी है जिसका प्रयोग कर दूध से मलाई निकाली जाती है उसी प्रकार से हम शिक्षा के द्वारा मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उनको उसकी क्षमता अनुसार प्रयास करते हैं। शिक्षा मनुष्य को मनुष्यता के आदर्शों तथा कर्मों का ज्ञान करा कर समाज उपयोगी बनाती है। अर्थात् शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनने के पथ पर अग्रसर करती है। इसके द्वारा मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शक्तियों का विकास होता है।

साहित्य का पुनरावलोकन :किसी भी शोध कार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व शोध समस्या से सम्बन्धित साहित्य के पुनरावालोकन की आवश्यकता होती है। इस जानकारी की भली–भाँति पुष्टि के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक तथा पूर्व में हुए शोध कार्यो के साहित्य की समीक्षा करनी होती है।**मेंहदी, एस0 (1979)** के अध्ययन में प्राप्त परिणामों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष में कहा गया कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की समुचित सुविधा व्यवस्था पायी गयी। विद्यालय में शिक्षण के समय अध्यापकों के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता था, जबकि महानगर पालिका द्वारा संचालित अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में इन सुविधाओं का अभाव था तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से निम्न स्तर की थी। इसमें यह भी पाया गया कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि महानगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों से उच्च स्तर की थी।**गुप्ता, एस0 पी0 –(1980)** ने 6–14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों अनामांकन, अनुपस्थिति और ड्राफ्ट की स्थिति एवं कारण का अध्ययन किया। इस अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष प्राप्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनामांकन अधिक परन्तु शहरी क्षेत्रों में अनामांकन से कम था। विद्यालय की सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या का अनामांकन की स्थिति से कोई सम्बन्ध नही था।**कपाड़िया, के0 पी0 (1984)** ने स्वतंत्रता के पश्चात (1947–1950) गुजरात राज्य के प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन किया और निष्कर्ष प्राप्त किया कि गुजरात में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति प्रशंसनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुजरात में अन्तिम तीन दशकों प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।**बुच, एम0 बी0 (1988)** ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पारिवारिक दशा, उनकी आवश्यकता तथा स्कूल जाने की प्रेरणा, बच्चों का सम्बन्धीय ज्ञान, बच्चों की गणित तथा गुजराती में योग्यता जानने के उद्देश्य से अध्ययन किया गया और निष्कर्ष प्राप्त किया कि शैक्षिक प्रेरणा के अलावा सभी

चरों का माध्य अन्तर विभिन्न आयु वर्गो के छात्रों का सांख्यिकीय दृष्टि से असंगत पाया गया।**गोविन्द तथा वर्गीस (1991)** ने भारत की बेसिक शिक्षा सुविधाओं की गुणवत्ता का अध्ययन किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं और स्थानीय पर्यावरण के स्तर का मूल्यांकन करना तथा विद्यालयी शिक्षा के परिणामों के उपलब्धि और सीखने वालों का स्तर (प्राथमिक कक्षाओं) को मापना था। इस शोध के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष में यह परिणाम निकला कि – विद्यालय द्वारा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और सीखने वालों की उपलब्धि ने विद्यालयी गुणवत्ता स्तर को प्रभावित किया।

पुष्पा, रश्मि (1997) ने प्राथमिक स्तर के कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के माता–पिता की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा व गणित में शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन लखनऊ विश्वविद्यालय में एम0 एड0 पाठ्यक्रम में लघु शोध ''प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में अध्ययन'' किया। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ती ने सीतापुर शहर के प्राथमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों का न्यायदर्श लिया, जिसमें छात्र–छात्राओं दोनों ने अध्ययन किया।**बोरा, सुनीता रानी (2000)** ने शोध हेतु सीतापुर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के 4–4 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया तथा इन विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु चुना। अध्ययन के प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों को बहुत आकर्षित करती है तथा बच्चों में सुनने व बोलने की क्षमता विकसित करती है।**शिखा (2002)** ने सीतापुर के प्राथमिक विद्यार्थियों के अकादमिक उपलब्धि तथा शैक्षिक साधनों का तुल्नातमक अध्ययन किया। अपने अध्ययन हेतु शोधकर्त्री ने सीतापुर शहर के सरकारी व निजी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा पाँच के विद्यार्थियों का अपने अध्ययन हेतु चयन किया तथा परिणामों व निष्कर्षो को प्राप्त करने में प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया।**कटियार, प्रीति (2005)** ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने एम0 एड0 पाठ्यक्रम के लघु शोध में ''प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के पठन कौशल, लेखन कौशल तथा गणित विषय में गणितीय कौशल का अध्ययन'' किया। अपने निष्कर्ष में शोधकर्त्री ने पाया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अधिकांश विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा में पठन कौशल का स्तर निम्न है एवं हिन्दी की अपेक्षा अंगेजी में निम्नतर है। इन विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान भी कम है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों का दोनों भाषाओं में लेखन कौशल निम्नस्तर का है। इसी प्रकार कौशल सामान्य स्तर का है एवं गणित के प्रत्ययों के ज्ञान कम है।

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति–भारत में वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में सरकारी विद्यालयों की संख्या

में महत्वपूर्ण गिरावट आई है (–10.39 प्रतिशत)। वर्ष 2015–16 में 113.08 मिलीयन सरकारी विद्यालया थे जबकि वर्ष 2010–11 में इनकी संख्या 126.20 मिलीयन थी। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में निजी विद्यालयों की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी। निजी विद्यालयों की संया में बढ़ोत्तरी लोगों की निजी विद्यालयों की रुझान को दर्शाता है।पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में अधिकांश विद्यालय सरकारी विद्यालय थे जबकि केरल, महाराष्ट्र तथा तमिल नाडु में गैरअनुदानित विद्यालयों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। आसाम, केरल तथा झारखण्ड में निजी गैरअनुदानित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का अनुपात अधिक था।

उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की प्रगति को सारणी 1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2017–18 में कुल विद्यालयों के सापेक्ष सरकारी विद्यालयों का अनुपात 69.31 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि लगभग एक तिहाई विद्यालय निजी विद्यालय थे। कुल प्राथमिक विद्यालयों में 69.39 प्रतिशत सरकारी विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 72.25 प्रतिशत सरकारी विद्यालय थे। माध्यमिक स्तर पर कुंल विद्यालयों के सापेक्ष 71.50 प्रतिशत निजी विद्यालय थे। वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2017–18 में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की श्रेणी में बढ़ोत्तरी हुई है तथापि सरकारी अनुदानित प्राथमिक विद्यामलयों की संख्या में गिरावट आई है।

उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की प्रगति

विद्यालयों की श्रेणी	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18
प्राथमिक विद्यालय	155011	155756	159686	164319
सरकारी विद्यालय	113566	113947	113927	113976
सरकारी अनुदानित विद्यालय	1405	617	475	364
निजी विद्यालय	37659	38748	38508	40082
मदरसा	2381	2446	6776	9897
उच्च प्राथमिक विद्यालय	62882	63551	63817	64231
सरकारी विद्यालय	46446	46431	46397	46411
सरकारी अनुदानित विद्यालय	2600	2605	2569	2543
निजी विद्यालय	13691	14332	14555	14919
मदरसा	145	183	296	358
माध्यमिक विद्यालय	4839	4830	5164	5253

सरकारी विद्यालय	1127	1160	1339	1382
सरकारी अनुदानित विद्यालय	27	22	33	68
निजी विद्यालय	3680	3644	3719	3756
मदरसा	5	4	73	47
सभी विद्यालय	252917	255967	265078	275278
सरकारी विद्यालय	162241	162645	162872	163274
सरकारी अनुदानित विद्यालय	9281	8362	8242	8270
निजी विद्यालय	77409	80746	83284	88415
मदरसा	3986	4214	10680	15319

स्रोतः बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ

वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2017–18 में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2017–18 में प्राथमिक विद्यालयों में 34.32 मिलीयन विद्यार्थियों का नामांकन हुआ जबकि वर्ष 2014–15 में 36.84 मीलियन विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या में लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्ग के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में इस अवधि में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2018 में प्रदेश के विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाओं तथा अन्य भौतिक सुविधाओं में आशातीत वृद्धि हुंई तथापि बच्चों द्वारा कम्प्यूटर का उपयोग, विद्युत संयोजन तथा उसकी उपलब्धता, पुंस्तकालय तथा पुस्तकों का बच्चों द्वारा उपयोग और बालिकाओं हेतु उपयोग योग्य शौचालय की उपलब्धता का अनुपात अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया।

प्राथमिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षा कं क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। सभी के लिए शिक्षा परियोजना अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के संजाल के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता युंक्त शिक्षा के लिए प्रयास किये गये जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से प्रदेश में सभी बच्चों के नामांकन, विद्यालयों में उनके ठहराव, शैक्षणिक वातावरण के सृजन तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है तथापि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तथा समयानुकूल शिक्षा की कमी, शिक्षकों का छात्रों के प्रति गैरमैत्री व्यवहार, विद्यालयों में शैक्षणिक तथा भौतिक सुविधाओं की कमी आदि प्रमुख बाधाएं रही हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है।

सुझावः

- अध्यापकों को अपनी परम्परागत अध्यापन प्रणाली में बदलाव लाना होगा जिससे कि शिक्षण सीख गतिविधियों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ सके। अध्यापकों को समूह चर्चा प्रणाली, परस्पर सम्पर्क प्रणाली, श्रव्य वं दृष्य उपकरण उपयोग, डिजिटल पद्धति आदि नवाचारी शिक्षण प्रणाली को अपनाना चाहिए। अध्यापकों को विद्यार्थियों के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

- विद्यार्थियों को मौलिक अध्ययन सामग्री, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य रोचक पाठ्यक्रम से परे पुंस्तकों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों तथा शैक्षणिक सरोकारों की समझ हो सके।

- विद्यालयों में आधारभूत संरचना तथा भौतिक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा, संचार सुविधा, डिजिटल पद्धति की शिक्षा, आडियो–विजुअल उपकरणों की उपलब्धता, पुस्तकालय सुविधा, खेलकूद मैदान तथा खेलकूद के उपकरण, विद्युत संयाजन तथा आपूर्ति, बेहर फर्नीचर आदि द्वारा विद्यालयों को आकर्षक शिक्षा केन्द्र बनाया जा सके।

- विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शिक्षकों की गैरशिक्षण गतिविधियेां में भागीदारी को कम करने की आवश्यकता है जिससे कि वह शिक्षण कार्य पर विशेष बल दे सकें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति तथा अन्य प्राथमिक विद्यालयों में अतिथि विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा समय–समय पर विद्यालयों में विशेष सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक मूल्यों तथा सरोकारों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को जागरुक किया जा सके।

- विद्यालयों की नियमित रूप से निगरानी की जाने की आवश्यकता है जिससे कि विद्यालयों का संचालन और विद्यार्थियों के शैक्षणिक निष्पादन का आंकलन किया जा सके। यह कार्य डायट तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शैक्षणिक मानकों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति को मजबूत किये जाने की आवक्ष्यकता है। इसके साथ ही साथ अभिभावक–शिक्षक बैठकों के अन्तराल को कम किये जाने की आवश्यकता है। अभिभावकों को अभिभावक–शिक्षक बैठकों में नियमित रूप से प्रतिभाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- ग्राम शिक्षा समिति को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ग्राम शिक्षा समिति के बेहतर संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की महति योगदान है। अतः ऐसी संस्थाओं द्वारा विद्यामलयों में शैक्षणिक परिवेश का सृजन किया जाना चाहिए।

- विद्यार्थियों को घरेलू कार्य दिये जाने हेतु बल दिये जाने की आवश्यकता है तथापि पिछड़े समुदायों से आये हुए विद्यार्थियों को विद्यामलय में अतिरिक्त समय देकर उनके घरेलू कार्यों तथा कमजोर विषयों में शैक्षणिक सहयोग–शिक्षण दिये जाने की भी आवश्यकता है जिससे कि विद्यार्थियों में हीन भावना उत्पन्न न हो।

सन्दर्भ –

1. मेंहदी, एस0 (1979)''बड़ौदा नगर में महानगर पालिका द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों तथा निजी अभिकरणों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक एवं उनमें उपलब्ध शिक्षण एवं अनुदेशन की सुविधाओं का अध्ययन'' शोध प्रबन्ध, बड़ौदा विश्वविद्यालय, बडौदा।
2. गुप्ता, एस0 पी0 –(1980) : ''प्राथमिक विद्यालयों में अनामांकन, अनुपस्थिति की ड्रापआउट की स्थिति एवं कारण '' शोध प्रबंध, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. कपाड़िया, के0 पी0 (1984) : ''स्वतंत्रताके पश्चात (1947 से 1980 तक) गुजरात राज्य के प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन'' शोध प्रबन्ध, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।
4. पुष्प, रश्मि (1997) :''प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में अध्ययन'' लखनऊ विश्वविद्यालय
5. बोरा, सुनीता रानी (2000) 'प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों पठन आदत को विकसित करने में शिक्षण तथा अधिगम सामग्री की पहचान करना'' शोध प्रबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. शिखा (2002) : '' सीतापुर के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि'' लघु शोध प्रबन्ध, एम0 एड0 पाठ्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
7. कटियार, प्रीति (2005) :'प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के पठन कौशल, लेखन कौशल तथा गणित विषय में गणितीय कौशल का अध्ययन'' लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।